



जबवीणा

स्वर जन-मन का...

□ वर्ष : 12 □ अंक : 23

□ लखनऊ, 21 मई, 2023

□ पृष्ठ : 8

□ मूल्य : 3 रुपये

लोककल्याण का आधार है सनातन धर्म: सीएम योगी

महाराजगंज। सीएम ने कहा कि चेतन जगत के प्रति हमारी श्रद्धा हमारी पहचान है और यही सनातन का आधार भी है, लोक कल्याण से जुड़ी हर क्रम सनातन का अंग है। दुनिया में तमाम धर्म, संस्कृति और पंथ आये और समाप्त हो गए, आगे भी तमाम आएंगे और जाएंगे लेकिन चीर सनातन धर्म आज भी उसी अवस्था में जीवंत है तो इसका एक मात्र कारण लोककल्याण की अवधारणा है। सृष्टि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म-संस्कृति की पहली विशेषता है। सनातन संस्कृति हमें कृतज्ञता का भाव सिखाता है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह बातें मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिले के प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर चौक परिसर स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा



कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि लोककल्याण ही धर्म का आधार है, धर्म हमें लोककल्याण को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कहा कि हनुमान जी

जब लंका में जा रहे थे तब पर्वत ने उनसे प्रश्न किया था कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? उन्होंने जवाब दिया था कि कोई आप पर कृपा करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन धर्म का कर्तव्य है। यही

इसका पहला लक्षण भी है। हर सनातन धर्मावलंबी इस भाव को ठीक से समझता है। उन्होंने कहा कि जीवन चक्र जड़-चेतन के बेहतर समन्वय से चलता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म ने वनस्पतियों,

जीव-जंतुओं के महत्व को समान रूप से स्वीकार किया है।

सीएम ने कहा कि चेतन जगत के प्रति हमारी श्रद्धा हमारी पहचान है और यही सनातन का आधार भी है, लोक कल्याण से जुड़ी हर क्रम सनातन का अंग है। दुनिया में तमाम धर्म, संस्कृति और पंथ आये और समाप्त हो गए, आगे भी तमाम आएंगे और जाएंगे लेकिन चीर सनातन धर्म आज भी उसी अवस्था में जीवंत है तो इसका एक मात्र कारण लोककल्याण की अवधारणा है, जो हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा प्रदान करती है। इस अवसर पर कथावाचक बालक दास महाराज, संतोष दास महाराज, रविन्द्र दास, त्यागीनाथ उर्फ फलहारी बाबा, केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी, विधायक जयमंगल कन्नौजिया, प्रेम सागर पटेल, ज्ञानेन्द्र सिंह, ऋषि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को -राहुल गांधी

नयी दिल्ली (यूनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति को संसद की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मई को संसद के



नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने बताया था कि नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया था। राहुल ने ट्वीट किया, "नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं।"

संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख तय की गई है।

उसी दिन हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर की जयंती है और कई विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्र निर्माताओं का 'अपमान' करार दिया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन पर तैयार की गई पुस्तिका के अनुसार, नये संसद भवन के बैठने की व्यवस्था होगी और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संयुक्त सत्र के दौरान सदन में 1,272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी।

आरक्षण के बहाने सियासत गरमाने में जुटे स्वामी प्रसाद दिया रामराज हटाओ- आरक्षण बचाओ का नारा

लखनऊ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित ट्वीट कर सुर्खियों में आ गए हैं। वह आरक्षण के बहाने सियासत गरमाने में जुटे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट किया है।

रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी करके विवादों में घिरे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब रामराज हटाओ- आरक्षण बचाओ का नारा देना शुरू कर दिया है। इसके जरिए वह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश की सियासत गरमाने में जुटे हैं। वह कहते हैं कि इस नारे के जरिए प्रदेश भर में जनजागरण करेंगे। लोगों को भाजपा सरकार की हर चाल से वाकिफ कराएंगे।

बसपा से वाया भाजपा होते हुए सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी की तो प्रदेश की सियासत



में हलचल मच गई। अपनी ही पार्टी के कई विधायकों की आलोचना के भी शिकार हुए। सपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से नवाजा। पार्टी के नेताओं के बीच स्वामी प्रसाद को दो ध्रुव नजर आए। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद अपने बयान पर अडिग रहे।

इस बीच उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा स्थापित करके दलितों और पिछड़ों के बीच संदेश देने का प्रयास किया। प्रतिमा

अनावरण समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण बचाने की अपील की। सपा अध्यक्ष हर कार्यक्रम में आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारते समय भी आरक्षण का ही दांव चला गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण का मुद्दा सामने आते ही स्वामी प्रसाद ने लपक किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि रामराज धोखा है।

सम्पादकीय

सुनहरा कल वर्तमान की कठिन सीढ़ियों से चढ़ कर ही बनता है

हमें सदैव वर्तमान में जीना चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ आगे सदैव अग्रसर होते रहना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को बड़ा बनाने या समृद्ध बनाने के लिए वर्षों की मेहनत अधिक प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ संयम एवं उच्च मनोबल की आवश्यकता होती है, तब जाकर ही राष्ट्र एक मजबूत तथा विकासवान राष्ट्र बन पाता है। आजादी के 75 वर्ष के बाद भारत ने विकास की गति को बहुत मजबूती के साथ थामा हुआ है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में युवा जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, आने वाले भविष्य में देश की बागडोर इन्हीं युवा हाथों में होने वाली है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आशाओं पर आकाश टिका हुआ है और निसंदेह आशा, उम्मीद, संभावना बहुत ही सारगर्भित एवं चमत्कारिक शब्द भी हैं। उम्मीद जो इतिहास में कई बार चमत्कार करती आई है। यह आशा एवं उम्मीद का ही प्रतिफल है कि हम सकारात्मक होकर उच्च मनोबल के साथ किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर यदि लक्ष्य मेडिकल साइंस में किसी नई दवा को इजाद करना हो या स्पेस रिसर्च में नई टेक्नोलॉजी लाना हो या देश में विकास की नई धारा को प्रवाहित करना हो, तो सकारात्मक ऊर्जा हमें इस संदर्भ में मदद करने वाला तत्व होता है। अच्छी और सही सोच हमेशा अच्छे परिणाम देने वाला होती है, पर बिना सकारात्मक सोच के और बिना किसी सार्थक परिणाम की कल्पना किए हुए उस पर पसीना बहाना बड़ा ही दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। अच्छे पद अथवा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी सकारात्मक सोच और उच्च मनोबल तथा संयम को लेकर ही आगे अपनी तैयारी करता है एवं उच्चतम अंक या उच्च पद की प्राप्ति करता है। कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में बिना पदक की लालसा के तैयारी नहीं कर सकता और पदक को लक्ष्य मानकर जब वह पूर्ण मनोबल के साथ आशाओं की लकीरों के मध्य वह जब अपना पसीना मैदान में बहाता है तो वह लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगातार अग्रसर होता है और उसे अंत में अपनी सकारात्मक ऊर्जा के कारण वह पदक अवश्य प्राप्त होता है। दार्शनिक भी कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक बेहतर और अच्छी शुरुआत सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। हम संभावनाओं के दम पर जो हमें निरंतर प्रेरित करती है अपना पहला कदम उठाकर सफलता सुनिश्चित करते हैं। जीवन की कटु सच्चाई तथा जिंदगी के उतार-चढ़ाव को झेलने के लिए एवं सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए हमें आशा एवं सकारात्मक सोच की सदैव मदद करती इसके बिना किसी सफलता के बारे में सोचना भी बेमानी होगा। संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने संपूर्ण मनोबल के साथ उस कार्य को अंजाम देने के लिए अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी होगी एवं लक्ष्य के साथ दे तथा साधनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर उस के संदर्भ में उसके अंतर्निहित हर तत्व को भलीभांति पहचान कर उस पर मेहनत करनी होगी अन्यथा बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि मेहनत और कठोर श्रम न किया जाए तो असफलता ही हाथ लगती है। यही वजह है कि जिन भी बड़े लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है निसंदेह उन्होंने कठिन परिश्रम अपने लक्ष्य के लिए किया था, है और करेंगे। हर बड़े कार्य को करने के लिए अच्छी योजना, अच्छा आकलन एवं उस सफलता को अपना बनाने के लिए सही विचार तथा नीतियां बनानी होंगी एवं अपने उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण तथा अवलोकन कर उसकी क्षमता का आकलन करना होगा। केवल हवा में सकारात्मक सोच और मनोबल के दम पर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तम एवं बड़े सकारात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बड़ी सोच अथवा मेहनत एक सुनियोजित नीति एवं पृष्ठभूमि में शांत चिंतन मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हमारे सामने जो उपलब्ध वर्तमान का समय है वर्तमान के अवसर संपूर्ण सदुपयोग कर भविष्य की तमाम सफलताओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। हमें सदैव चौकन्ना रहकर जो हमारे सामने समय सीमा है एवं समय के अवसर हैं उन्हें पहचान कर उसका संपूर्ण दोहन कर उपलब्ध संसाधनों का परीक्षण कर समेकित रूप से सब का समुचित उपयोग कर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जागृत होना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा की कोरोना काल में हमें आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए और अवसर ही हमें किसी भी विकट परिस्थिति से लड़ने एवं उस पर नियंत्रण रखने की शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह सकारात्मक सोच का ही परिणाम है की कोविड-19 के संक्रमण में भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में उस पर प्रभावी नियंत्रण किया एवं उस पर विजय प्राप्त की है।

एक करोड़ रोजगार और अग्रसर उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और फरवरी में सम्पन्न हुए निवेशकों के तीन दिवसीय महाकुंभ का परिणाम दिखाई पड़ने लगा है। जिस तरह से निवेशकों के प्रति प्रदेश सरकार ने दरियादिली दिखाई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था, सड़क परिवहन और ऊर्जा आदि के क्षेत्र में बेहतर माहौल तैयार किया है उसका परिणाम आने वाले दिनों में धरातल पर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश एक करोड़ रोजगार के अवसर देने की ओर अग्रसर हो चुका है। प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी और एटा में 4500 करोड़ के निवेश के साथ लगभग 6000 रोजगार के अवसर धरातल पर फलीभूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहली बार इन पाँच जिलों के प्रस्ताव 100 प्रतिशत आनलाइन प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जा चुके हैं। जैव ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीनेडा ने सात निवेशकों के 325 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यही नहीं प्रदेश में पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला चन्दौली जिला प्रदेश सरकार की बेहतरीन कार्यशैली के चलते निवेशकों के लिए सबसे अधिक निवेश करने वाला जिला बना गया है। चार निवेशकों द्वारा चन्दौली जिले में 7020 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। अमेठी में 4,761 करोड़ का निवेश करने वाली 30 इकाईयाँ तो पूर्वांचल में 20,189 करोड़ खर्च कर 65 इकाईयाँ उद्योग स्थापित करने को तैयार है। पश्चिमांचल में 12,051 करोड़ का निवेश के साथ 70 और मध्यांचल में 5200 करोड़ का निवेश कर 60 तो सबसे पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड में 2872 करोड़ के निवेश के साथ चार इकाईयों की स्थापना अंतिम दौर पर है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इतना निवेश होने के बाद प्रदेश में दस लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर अगले तीन माह में फलीभूत हो जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की कड़ी में राजधानी लखनऊ में आयोजित निवेशकों के तीन दिवसीय महाकुंभ में नया इतिहास लिखा जा चुका है। यूपीजीआइएस-23 के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तावित निवेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति देगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का जरिया बन युवाओं के सपनों को भी साकार करेगा। ज्ञात हो कि इनवेस्टर समिट में 41 देशों से 400 से अधिक प्रतिभागी के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से 10 हजार छोटे निवेशक इस आयोजन का हिस्सा बनें थे। उस दौरान विदेश से भी 7.12 लाख

करोड़ निवेश की उम्मीद की गई थी। देश की सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी ग्रुप ने इस दौरान खुदरा और नये ऊर्जा कारोबार समेत दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वायदा किया था। ऐसे में यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रबल सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। हाल में गलगोटिया विश्वविद्यालय के चांसलर सुनील गलगोटिया और सीईओ ध्रुव गलगोटिया से हुई मुलाकात में उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि राज्य में निवेशकों द्वारा किए जा रहे 32 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश से आने वाले दिनों में यहां करीब एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। सुनील गलगोटिया ने इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री को देते हुए कहा कि यह सब इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यही कारण है कि निवेशक कहीं और जाने के बजाय अब भयमुक्त होकर प्रदेश में काम कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वयं की व्यथा साझा करते कहा कि कानून व्यवस्था बेहद लचर होने के कारण गलगोटिया समूह को भी शुरुआत में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ा था। हर समय भय के माहौल में काम करना पड़ता था पर आज मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व के चलते हम बिना किसी डर के प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तायुक्त विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की पहल पर बनाए गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2019 का उल्लेख करते हुए आश्चर्य किया कि इसके जरिए हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे उत्तर प्रदेश देश में तेजी से उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों वाला हब बनने की ओर अग्रसर है। सुनील गलगोटिया ने इस बात से पूर्ण सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री को इस दिलचस्प तथ्य से अवगत कराया कि पहले जहां उत्तर भारत के युवा उच्च शिक्षा के लिए दक्षिण भारत का रुख करते थे, वहीं सरकार का सक्रिय सहयोग मिलने के बाद माहौल पूरी तरह बदल - जाने से अब दक्षिण भारत सहित अन्य राज्यों के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों का रुख करने लगे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रस्ट्रक्चर को तेजी से

विश्वस्तरीय बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से समूचे प्रदेश के विकास को और अधिक गति मिलेगी। इससे राज्य के युवाओं को हर स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार मिलने से उनमें उत्साह का संचार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के संकल्प, इच्छाशक्ति और विजन से प्रदेश निश्चित ही देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम करेगा। यही नहीं छह साल पहले तक जिस गीड़ा में निवेश करने से निवेशक कतराते थे, बदले माहौल में वहां बड़ी इंडस्ट्री लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठित उद्योग समूह मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंडीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्लांट के पूरी क्षमता से संचालित होने के बाद दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष और पांच हजार लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा। गीड़ा की तरफ से एएल-2 सेक्टर-23 में आर्वाइट 82 एकड़ क्षेत्रफल में फैले और 550 करोड़ रुपये के निवेश वाले इस प्लांट की स्थापना का कार्य 2020 में शुरू हुआ था। इसमें टीएमएक्स (थर्मैक्स पॉवर्ड) सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। इंडीग्रेटेड स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता तीन लाख टन प्रति वर्ष की है। यहां 30 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। अंकुर उद्योग लिमिटेड ने प्लांट के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपये के निवेश का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) भी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में किया था। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में आए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम हो रहा है। भूमि पूजन समारोह में यूपीसीडा 40 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव धरातल पर उतारेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सितंबर-अक्तूबर में प्रस्तावित पहले भूमि पूजन समारोह के लिए आठ लाख करोड़ के पांच हजार से अधिक एमओयू को छंटे गए हैं। इसके तहत यूपीसीडा ने 40 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के लिए जमीन प्राप्त कर ली है। जल्द उन्हें भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपीसीडा को भूमि पूजन समारोह के लिए 1.6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का लक्ष्य दिया गया है। यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी के अनुसार 600 निवेशकों से कुल 3.18 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए इन्हें पांच श्रेणियों में बांटा गया।

जापान में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नयी दिल्ली (यूएनएस)। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात सार्थक रही। हमने व्यापार, नवोन्मेष, विज्ञान और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट कर बताया कि व्यापार रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मुलाकात में बात हुई है। लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक ने रविवार को मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता की समीक्षा हुई है। मोदी और सुनक यहां हिरोशिमा में जी7 देशों के शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। दोनों ने काफी देर तक खड़े रहकर बातचीत भी की। दोनों की मुलाकात की कई फोटो सोशल मीडिया पर बायरल हो रही हैं।

डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटेन के



प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास) ने कहा कि दोनों नेताओं ने जापान में वार्ता के दौरान 'महत्वाकांक्षी' एफटीए के लिए काम करने पर सहमति जताई। इससे पहले पिछले नवंबर में इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन के बाद से उनकी दूसरी निजी बैठक में देशों के बीच गहरे संबंधों पर चर्चा हुई। डाउनिंग स्ट्रीट ने यह संकेत भी दिया कि सुनक अपनी पहली भारत यात्रा के लिए इस साल के अंत में नयी दिल्ली आ सकते हैं। वह जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आएंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने

कहा, "नेताओं ने ब्रिटेन और भारत के बीच गहरे संबंधों, हमारे मानवीय संबंधों और लोकतंत्र तथा निष्पक्ष और मुक्त व्यापार के महत्व पर विचार किया।" प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि इस महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम किया जाएगा।

इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात सार्थक

रही। हमने व्यापार, नवोन्मेष, विज्ञान और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट कर बताया कि व्यापार रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मुलाकात में बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में सार्थक बातचीत हुई है।

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, %व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन के बीच एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) से जुड़ी वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लेने के साथ-साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा कि मोदी और सुनक ने व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच परस्पर संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

तेज रफ्तार कार ने छह लोगों को रौंदा, तीन मौत

जयपुर राजस्थान में जयपुर के कोटखावदा थाना क्षेत्र में रविवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की चपेट में आने से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परिवार के सभी छह सदस्य दो दिन पहले हरिद्वार गए थे और रविवार सुबह वहां से लौटे थे तथा घर से कुछ दूरी पर परिजनों का सड़क किनारे इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सभी को कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि घटना जयपुर जिले की चाकसू तहसील में डोई की ढाणी के पास हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद कार चालक दुर्घटनास्थल पर कार छोड़कर फरार हो गया। कोटखावदा सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मदन चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में एक महिला और उसके बेटे सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आशंका है कि कार चालक नशे में था क्योंकि वाहन से शराब की बोतल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि रामनगर रोड स्थित डोई की ढाणी निवासी मदन की 17 मई को बीमारी के चलते मौत हो गयी थी।

दो हजार का नोट और जनता

रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपए के नोटों को बन्द करने के फैसले को आम जनता ने आश्चर्य के रूप में लिया है और 2016 की नोटबन्दी के समय इनके जारी करने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। बेशक दो हजार के नोटों का प्रचलन खुले बाजार में बहुत कम संख्या में ही था मगर इनके प्रचलन से ही बाहर करने के फैसले की तार्किकता को आलोचक इस कसीटी पर कस कर रहे हैं कि बहुत कम समय के अन्तराल में ही मुद्रा के सबसे बड़े नोट को बन्द कर देने से लोगों में मुद्रा की विश्वसनीयता पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दो हजार के नोटों को बन्द करने से अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा मगर यह सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा कि आखिरकार इसका असल उद्देश्य क्या है? रिजर्व बैंक ने जनता द्वारा इन नोटों को बदलने के लिए 30 सितम्बर तक का समय दिया है जिसके लिए कुछ नियम भी घोषित किये हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति 20 हजार रुपए तक के दस नोट बैंकों में जाकर बदलवा सकता है। बैंक के अनुसार फ्लिहाल तीन लाख 72 हजार करोड़ रुपए के दो हजार के नोट बाजार में हैं जो विभिन्न

धनराशियों में प्रचलित नोटों की संख्या का 10.80 प्रतिशत के लगभग ही है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 31 लाख करोड़ रुपए के प्रचलन में नोटों की धनराशि 31 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। रिजर्व बैंक ने साथ में यह भी कहा है कि 30 सितम्बर के बाद इनका बाजार में प्रचलन बेशक बन्द हो जायेगा मगर यह वैध मुद्रा बनी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि दो हजार के नोटों को 30 सितम्बर के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने पास रखता है तो वह जुर्म नहीं होगा जबकि 8 नवम्बर 2016 को जब एक हजार व पांच सौ रुपए के नोट बन्द किये गये थे तो सरकार द्वारा इन्हें बदलवाने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद इन्हें अपने पास रखना जुर्म की श्रेणी में आ गया था और यह वैध मुद्रा नहीं रही थी।

इस फैसले से बिना शक आम जनता में अफ़ा-तफ़री मच गई थी और नोट बदलवाने के लिए बैंकों के सामने लम्बी-लम्बी लाइनें लग गई थीं। जाहिर है कि रिजर्व बैंक का यह फैसला 8 नवम्बर जैसा नहीं है और यह किसी विशिष्ट शृंखला के नोट बन्द किये जाने के फैसले के समरूप ही है परन्तु अंतर मात्र इतना ही है कि सभी शृंखलाओं के

दो हजार के नोट एक ही इन्क के में बाजार से बाहर किये जा रहे हैं। तर्क रखा जा रहा है कि दो हजार रुपए का नोट पिछले लगभग एक साल से भारत के बाजारों विशेष कर छोटे व मझोले दुकानदारों के साथ होने वाले लेन-देन में देखा ही नहीं जा रहा है तो इसका असर सामान्य जनता पर नहीं पड़ेगा और केवल उन्हीं लोगों को फ़िक्र होगी जिन्होंने इन नोटों को जमा करके रखा हुआ है। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि अधिसंख्य नोट कालेधन के रूप में पैसे वालों की तिजारियों में बन्द हैं। मगर यह तर्क पूर्णतः जायज इसलिए नहीं है क्योंकि कोई औसत दर्जे का नागरिक भी बड़े नोटों का संग्रह अपनी गाढ़ी बचत के रूप में सुविधामय मानते हुए कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा। यह भी एक पक्षीय तर्क है क्योंकि भारत की 140 करोड़ आबादी के बीच केवल 60 करोड़ ही स्मार्ट मोबाइल फोन हैं और भारत के बाजारों में 36 लाख करोड़ के नोट प्रचलन में हैं जो कि नोटबन्दी के समय प्रचलित मुद्रा से डेढ़ गुना से भी बहुत ज्यादा है अतः नकद रोकड़ा लेन-देन भारत में कम नहीं हुआ है लेकिन इससे दो हजार रुपए

के नोटों का कोई फ्लिहाल खास लेना-देना है, हां यह जरूर कहा जा सकता है कि समाज में इससे धनपतियों की मुश्किलों में कुछ लोग ईर्ष्या के चलते दिमागी खुशी पाने का सुख जरूर अनुभव कर सकते हैं क्योंकि 90 प्रतिशत जनता के पास दो हजार रुपए के नोट हैं ही नहीं। 2016 की नोटबन्दी का असर सामाजिक ताने-बाने पर इसी 'पर दुखे परम सुख' मानसिकता की वजह से ही हा था। तब लोगों ने समझा था कि इस बहाने काला धन बाहर आ जायेगा और जिन लोगों ने काली कमाई करके अपनी कोठियां खड़ी की हैं और ऐश-ओ-इशरत का सामान जोड़ा है उनको हिसाब देना पड़ेगा।

मगर काला धन फिर भी वापस नहीं आया और उतना ही धन वापस बैंकों में पहुंच गया जितनी की कुल मुद्रा प्रचलन में थी। दो हजार के नोट तो 30 सितम्बर के बाद भी वैध ही रहेंगे। हां इससे इतना जरूर होगा कि पुराने व कटे-फटे नोट बदलवाने वाले लोगों का धंधा फिर से थोड़ा उभार ले लेगा।

2013-14 में भी पांच-छह साल पहले छपी शृंखला के नोटों को बन्द कर दिया गया था। अतः रिजर्व बैंक का तर्क है कि दो हजार रुपए के नोट 2017 में भी आखिरी बार छापे गये थे अतः उनकी हालत खराब हो गई होगी इसलिए वो वापस लिये जा

रहे हैं। मगर तर्क यह है कि जब ये नोट बाजार में प्रचलन में ही बहुत कम हैं और तिजोरियों में ही बन्द पड़े हैं तो इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? यह तथ्य तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 2016 की नोटबन्दी के बाद उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा को रिकार्ड तीन-चौथाई बहुमत मिला था मगर पंजाब राज्य में कांग्रेस विजयी रही थी। इसकी वजह उत्तर प्रदेश में जातिवादी प्रमुख समाज के चलते लोगों का अधिक गरीब होना भी माना गया था जबकि पंजाब में जातिवाद जैसी कोई समस्या नहीं रही है।

जाति के आधार पर पंजाबी समाज में सामाजिक भेदभाव की परंपरा नाम मात्र की ही है। बड़े नोट राजनैतिक दल भी संभाल कर रखते हैं और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव नवम्बर-दिसम्बर महीने में ही होंगे अतः रिजर्व बैंक के फैसले का प्रभाव राजनैतिक भी हो सकता है। खैर जो कुछ भी हो मगर इससे सामान्य नागरिक को चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। उसकी चिन्ता केवल यही हो सकती है कि दूर सफ़ पर जाते समय वह अपनी रकम दो हजार रुपए के नोटों में बदलवा कर ज्यादा सुरक्षित तरीके से ले जाया करता था। वैसे अमेरिका में भी सबसे बड़ा नोट एक सौ डालर का ही है।

कैडेटों के रोमांचक प्रदर्शन के साथ 10-दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण नौ सेना शिविर का समापन

लखनऊ (यूएनएस)। नेवल एनसीसी कैडेटों के 10-दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन 20 मई को कैप फायर के दौरान ला-मार्टिनियर कॉलेज में एक शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। कैडेटों ने मुख्य अतिथि, श्रीकालांडलमैक फारलैंड, प्रिंसिपल ला-मार्टिनियर कॉलेज, तथा कैप्टन (भारतीय नौ सेना) नवेंदु सक्सेना, कमांडिंगऑफिसर एवं कैप कमांडेंट का स्वागत एक प्रभावशाली सेमाफोर प्रदर्शन के साथ किया, जोकि नौ सेना में ध्वजों का उपयोग करते हुए एक संदेश प्रणाली है। एक साहसी अश्वारोही प्रदर्शन, मरीन कमांडो ड्रिल, योद्धा नौ सैनिकों पर आधारित एक मूक अभिनय, तथा ब्रैंड प्रदर्शन आदि उल्लेखनीय प्रदर्शन थे। अपने संबोधन के दौरान, श्रीमैकफारलैंड ने नौ सेना के मुख्य प्रशिक्षक, पैटी ऑफिसर कृष्ण तिवारी व उनकी टीम को एनसीसी कैडेटों को उच्च स्तर का नौ सेना प्रशिक्षण प्रदान करने और उनमें उत्तरदायित्व, गर्व और सकारात्मकता की भावना विकसित

करने के लिए बधाई दी। उन्होंने यह भी बताया कि विविध पृष्ठ भूमि से आने वाले एनसीसी कैडेटों को समान बर्ती बड़िल उनके बीच एकता और अनुशासन के मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। तत्पश्चात स्पेंस हॉल में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान, कैप्टननवेंदु सक्सेना ने कैडेटों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कैप के लिए कॉलेज परिसर और खेल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रिंसिपल लामार्ट का विशेष आभार व्यक्त किया। शिविर के दौरान, लखनऊ के 14 स्कूलों और कॉलेजों के 331 कैडेटों, बालक एवं बालिकाओं ने एध्वीधरी प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया। इस शिविर के एकउद्देश्य कैडेटों को समुद्र में नौ सेना कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन से परिचित कराना था, साथ ही उन्हें बोट पुलिंग, सीमैनशिप, ड्रिल, तैराकी, फायरिंग, हथियार संचालन, परेड प्रशिक्षण और शिप मॉडलिंग जैसी नौ सैनिक गतिविधियां सिखाना था। प्रशिक्षण

प्रभारी, पैटी ऑफिसर कोमल सिंह ने मीडिया को बताया कि इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों ने अत्यधिक जोश व हिम्मत का परिचय दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि नौ सैनिकों की टीम के सदस्य संदीप पाल, अजय मौर्य, आशुतोष सिंह, अजीत यादव, अतुल गुप्ता, सतीश कुमार और सरस द्विवेदी ने सभी गतिविधियों के सुरक्षित एवं कुशल संचालन करने हेतु कैडेटों के साथ दिन-रात कार्य किया, जबकि प्रधान सहायक मनोज शाह, नागेश द्विवेदी और वीनू सिंह ने सभी प्रशासनिक, प्रलेखन एवं लेखा कार्य कुशलता से पूरे किए। सब लेफ्टिनेंट प्रणव मिश्रा तथा अन्य सहयोगी एनसीसी अधिकारी-जोसेफ मसीह, विमलेश गुप्ता और देवेन्द्र सिंह ने कैडेटों के उन्मुखी करण और प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैप कमांडेंट ने युवा कैडेटों को मार्गदर्शन देने और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में सभी एएनओ की भूमिका की सराहना की।

नर्स का तीन युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग, धोखा देने पर तीनों ने मिलकर प्रेमिका की कर दी हत्या

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में एक ट्रेनी नर्स की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस नर्स को पुलिस सुसाइड मानकर जांच कर रही थी अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने हत्या की गुन्थी को सुलझाते हुए बताया कि मृतक नर्स का तीन युवक से प्रेम प्रसंग था। जब इसकी जानकारी एक दूसरे को हुई तो तीनों ने मिलकर नर्स की हत्या का योजना बना डाली। पुलिस ने बताया कि नर्स अस्पताल में इयूटी करने के बाद घर जा रही थी इसी बीच उसका प्रेमी उस मिलने के बाग में बुला लिया। नर्स प्रेमी के कहने पर बाग में पहुंच गई। इसके पहले पर दो लोग वहां पर मौजूद थे। जहां पर तीनों ने मिल कर उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। आरोपियों अपने जुर्म को छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर मौके फार हो गए थे।

पुलिस ने बताया कि रहीमाबाद निवासी 17 वर्षीय ट्रेनी नर्स एक निजी अस्पताल में काम करती थी। 10 अप्रैल की शाम वह लापता हो गई थी। दूसरे दिन गोस्वा गांव के रेलवे फटक के पास ट्रैक किनारे उसका शव पड़ा मिला था। मिले शव की शिनाख्त कराई तो युवती की पहचान मलिहाबाद निवासी के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने संदेह के आधार पर परिजनों ने दो पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने तफ्तीश की तो नामजद आरोपियों की भूमिका नहीं मिली। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने जांच के लिए पुलिस की टीम और इलेक्ट्रॉनिक की मदद ली गई। मृतक की मोबाइल कॉल डिटेल् से पता चला कि युवती गायब होने से पहले एक युवक से बात की थी। पता चला कि अमित अवस्थी नाम के शख्स से ट्रेनी नर्स का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन बाद न्यू मेडिकल्स अस्पताल के डॉक्टर अंकित सिंह व अमित के दोस्त दिनेश मौर्य के भी संपर्क में वह आ गई थी। उन्होंने बताया कि उसके बाद वह तीनों से बात करने लगी। जब इस बात की तीनों को पता चला तो तीनों उसकी हत्या कर दी उसके बाद शव ट्रैक किनारे फेंक दिया था। फिलहाल आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

100 घंटे में 100 किमी सिक्स लेन रोड तैयार, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड पीएम नरेन्द्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया सेलिब्रेट

लखनऊ (यूएनएस)। गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे यानि एनएच-91 पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछकर रोड बनाकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है इस रोड को बनाने में 200 रोडरोलर और करीब दो हजार से ज्यादा मजदूर लगे। सिक्स लेन हाईवे की इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेलिब्रेट किया। इससे पहले 100 घंटे में 75 किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड था। इस सिक्स लेन हाईवे को बनाने में खूबसूरती का बेहद ख्याल रखा गया है। हाईवे के बीचोंबीच डिवाइडर पर हरियाली है। कुछ जगह डिवाइडर तो कुछ जगह साइड वॉल पर प्रॉपर लाइटिंग है। 2011 में एनएचएआई ने इस हाईवे को फेर लेन बनाया था। अब सिंगापुर की क्यूब हाईवे कंपनी के सहयोग से इसे सिक्स लेन बनाया जा रहा है। करीब दो हजार मजदूरों ने दिन रात 100 घंटे लगातार काम किया तो 100 किलोमीटर रोड तैयार कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग पर उल्लेखनीय उपलब्धि। यह बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए गति और आधुनिक तरीकों को अपनाने दोनों को दिए गए महत्व को प्रकट करता है।



अटेवा की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक, पुरानी पेंशन बहाली लोकसभा चुनाव का होगा अहम मुद्दा

भविष्य निधि ट्रस्ट घोटाले की जांच प्रभावित करने के लिये हटाये गये निर्वाचित ट्रस्टी

ट्रस्ट में सीपीएफखाताधारकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की आशंका नामित किए कार्मिक ट्रस्टीज के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग

लखनऊ (यूएनएस)। कार्मिक ट्रस्टी इं जय प्रकाश एवं चन्द्रभूषण उपाध्याय ने संयुक्त रूप से प्रेसनोट जारी कर आरोप लगाया है कि 19 मई को अध्यक्ष पावर कारपोरेशन लि.अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कार्मिक ट्रस्टीज इं जय प्रकाश एवं चन्द्रभूषण उपाध्याय को ट्रस्ट के नियमों के इतर ट्रस्टी पद से निलंबित दर्शाकर उनके स्थान पर अवैधानिक रूप से अन्य कार्मिक ट्रस्टी नामित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। यह खाता धारकों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2004 में ट्रस्ट गठन के पश्चात से अक्टूबर 2020 तक नियमों के इतर अवैधानिक रूप ट्रस्ट का संचालन किए जाने के कारण ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हुई जिस प्रकरण में सीबीआई द्वारा जांच के साथ ही उच्चतम न्यायालय में वाद प्रक्रियाधीन है। इसी मध्य नवम्बर 2020 में ट्रस्ट के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होकर वैधानिक

रूप से ट्रस्ट का गठन हुआ। तदन कार्मिक ट्रस्टी इं जय प्रकाश, चन्द्रभूषण उपाध्याय एवं कलीम कुरैशी निर्वाचित हुए। कार्मिक ट्रस्टीज एवं नियोक्ता ट्रस्टीज के संयुक्त रूप से बोर्ड का गठन हुआ। इन कार्मिक ट्रस्टी द्वारा जारी दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर ट्रस्ट के कार्यों में गुणात्मक सुधार एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाये जाने का प्रयास किए गए 19 मई को अध्यक्ष पावर कारपोरेशन लि.अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा निर्वाचित कार्मिक ट्रस्टी इं जय प्रकाश एवं चन्द्रभूषण उपाध्याय को ट्रस्ट के नियमों के इतर ट्रस्टी पद से निलंबित दर्शाकर उनके स्थान पर अन्य कार्मिक ट्रस्टी नामित किए जाने का आदेश जारी किया गया। दोनों का आरोप है कि यह आदेश अवैधानिक है, जो ट्रस्ट में पूर्व में हुए अनियमितता एवं अरबों रुपये के घोटालों की जांच पर पर्दा डालने की मंशा से किया जाना परिलक्षित होता है। कार्मिक ट्रस्टीज जय प्रकाश एवं चन्द्रभूषण द्वारा जारी संयुक्त बयान में ट्रस्ट की गतिविधियों पर चिन्ता एवं आपत्ति जाहिर किया

गया। उन्होंने यह भी कहा, ट्रस्ट के निर्णय से ऊर्जा निगमों में 35000 सीपीएफखाताधारकों, कार्मिकों के जनादेश के साथ छलावा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है। सीपीएफखाताधारकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं उनके संचित निधि की असुरक्षा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु ट्रस्ट के चेयरमैन को पत्र लिखकर मांग की गई कि अवैधानिक आदेश तत्काल निरस्त कर ट्रस्ट का संचालन नियमों के अनुकूल किया जाये।

29 मई को होगा मतदान और मतगणना

लखनऊ (यूएनएस)। विधान परिषद की दो सीटों के लिए दाखिल चारो नामांकन पत्र चुनाव आयोग ने परीक्षण में सही पाये। सोमवार 22 मई को एमएलसी चुनाव में नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। कोई प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं लेता है तो 29 मई को विधान परिषद की रिक्त दोनों सीटों के लिए मतदान होगा।

डूंगन ने जी 20 से किया किनारा और जी 7 का किया कड़ा विरोध

संजीव ठाकुर

जी7 के सदस्यों में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर चीन तुर्की और पाकिस्तान की जान जला दी है। मोदी का वहां सभी देशों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जी 20 के संयुक्त देशों ने एक बयान जारी कर ताइवान पूर्वी और दक्षिण चीन सागर तथा लेह लद्दाख में चीन की आक्रामकता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और संयुक्त रूप से दिए गए बयान में कहा कि वह चीन के साथ रचनात्मक और स्थिर संबंध बनाना चाहते हैं, इस बयान में चिंता व्यक्त की गई है कि चीन ताइवान पूरी और दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रूप अपनाया हुआ है जो अत्यंत निंदनीय है इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन ने इसका विरोध करते हुए कहा की बीजिंग और चीन सागर में बयान देना बीजिंग के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने के समान है। हिरोशिमा में जी7 के मंचर ना होते

हुए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर और संयुक्त रूप से चीन और पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का खुलकर विरोध किया गया है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उनसे ऑटोग्राफ लेने की इच्छा जाहिर की है। यह गर्मजोशी से किया गया स्वागत की एक कड़ी थी। भारत में भी इस मंच से हुंकार भरते हुए चीन और पाकिस्तान के बर्ताव को लेकर खुला विरोध किया है। भारत सहित 7 देशों ने विश्व की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ सहयोग करने की जरूरत पर जोरदार वकालत की है और यह भी कहा है कि दुर्भावनापूर्ण इरादों और जोर जबर्जस्ती की हरकतों पर खुलकर विरोध किया जाना चाहिए आगे यह भी चिंता व्यक्त की गई है कि तिब्बत हांगकांग और लद्दाख सहित चीन द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर विरोध दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिनजियांग में बीजिंग पर हजारों उईगर मुसलमानों पर जबरन

श्रम शिविरों में बंद रखने का आरोप भी लगाया है। मानव अधिकारों के उल्लंघन और आतंकवादी हरकतों में शामिल चीन और पाकिस्तान इस बयान से तिल मिलाकर रह गए हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर में जी 20 देशों का चीन तुर्की सकूदी अरबिया ने किनारा कर लिया है और उन्होंने इस मीटिंग में शामिल ना होने का पंजीयन भी नहीं कराया है ऐसे में चीन की जी-20 बैठक में शामिल होना असंभव प्रतीत हो रहा है। यह बात वैश्विक रूप से सर्व विदित है कि भारत के प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता चरम पर है और भारत के राजनीतिक संबंध दुनिया के सभी देशों से मधुर भी हैं। भारत की अध्यक्षता में पर्यटन पर जी-20 समूह के तृतीय वर्किंग ग्रुप की तीन दिवसीय बैठक कागा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही चीन पाकिस्तान और तुर्की भारत का लगातार विरोध कर रहे हैं और यह पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है बैठक में 70

देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जम्मू-कश्मीर में उन्होंने अपना विश्वास जताया है। जी-20 की बैठक में भारत की अध्यक्षता करना भारत के वैश्विक स्थापना को एक नया स्थान दिलाएगा और जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के लिए मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए जी-20 सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम होगा और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया आयाम भी साबित होगा। यह बात बताने योग्य है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भेजकर वहां हमले करवाता रहा है और गुलमर्ग में सरकार की खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य को गिरफ्तार किया है जिसके कारण विदेशी मेहमान गुलमर्ग की वादियों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। यह आतंकी गतिविधि जी-20 की बैठक में विघ्न डालने के लिए की गई है। चीन और पाकिस्तान का अब जी 20 तथा जी7 के देश खुलकर विरोध कर रहे हैं ऐसे

में चीन की बीखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है इन बैठकों के परिणाम स्वरूप डूंगन की नई चाल सामने आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्राइ की बैठक में मोदी का स्वागत करते हुए उनकी वैश्विक लोकप्रियता का जिक्र किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके ऑटोग्राफ मांग लिए और पूछा कि कितनी बड़ी भीड़ को कैसे संतुलित करते हैं। मोदी आगामी समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण में अमेरिका प्रवास पर जाने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का दौरा पूरा करने के बाद रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे वहां पर एयरपोर्ट में राष्ट्रपति जेम्स मारपे द्वारा मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इतनी ज्यादा वैश्विक मान्यता भारत के प्रधानमंत्री को मिलने से निश्चित तौर पर चीन-पाकिस्तान तुर्क और कुछ अन्य देशों के हुक्मरानों को तकलीफ तो ज्यादा हुई है।

भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय की आज जयंती है। जिस वक्त अबोध बच्चों की शादी, विधवा का पति की चिता पर चढ़कर सती हो जाना और पर्दा करना समाज में सामान्य चलन था, उस वक्त राजा राममोहन राय ने धर्म के नाम पर चल रही इन अमानवीय प्रथाओं को खत्म करने के लिए अथक मेहनत की। चाहे बचपन में विवाह हो या अकाल मौत के लिए धकंला जाना हो, स्त्री को केवल इसलिए ये त्रासदियां भुगतनी पड़ती थीं, क्योंकि वो पुरुष सत्तात्मक समाज में जन्मी। राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों के व्यापक असर और महिलाओं की पीड़ा को समझा और उसके खिलाफ आवाज उठाई। देश के अलग-अलग हिस्से में कई और लोगों ने इसी तरह महिला उत्थान के कार्य किए। देश आजाद हुआ तो संविधान के जरिए महिलाओं के अधिकार रेखांकित किए गए। समय के साथ जागरूकता आई तो महिलाओं के हक में कई कानून बने, कई कानूनों में सुधार किए गए, ताकि स्त्री-पुरुष बराबरी की आदर्श स्थिति लाई जा सके। मगर आज जो हालात हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि देश को एक और पुनर्जागरण की जरूरत है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय पर रविवार को आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए देश में

एक और पुनर्जागरण की जरूरत

कई कानूनों को लागू किए जाने के बावजूद वो अक्सर उन कानूनों का लाभ उठाने में असमर्थ होती हैं। जब न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ये बात कह रहे थे, तब कोलकाता से बहुत दूर रोहतक के महम में खाप पंचायत हो रही थी। और एक खाप पंचायत दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रही थी। दोनों पंचायतें महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए हुईं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में इस पर मौन पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों जापान में हैं। रूस से युद्धरत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की से मुलाकात में उन्होंने कहा कि बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। श्री मोदी ने भारत की नीति-रीति के अनुरूप ही विचार रखे। लेकिन इस विचार को वे देश में अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं, यह समझ से परे है। पिछले महीने की 23 तारीख से जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है। यानी एक महीना होने में एक ही दिन बच गया है। बीते अनुभव यही बता रहे हैं कि मोदी सरकार में कोई भी धरना-प्रदर्शन लंबा ही चलता है, क्योंकि इंसाफ की मांग करने वालों का चीखते-चीखते गला सूख जाता है, मगर सरकार के कानों तक आवाज पहुंचती ही नहीं है। शाहीन बाग का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, या मोदी सरकार के गठन के फौरन बाद



2015 में हुआ एफ्टीआईआई के छात्रों का आंदोलन हो, सब लंबे खिंचे क्योंकि संवाद का अभाव था। इसलिए पहलवानों का आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा, कहा नहीं जा सकता। कितनी हैरानी की बात है कि देश के नामी-गिरामी पहलवान यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर ले-दे कर दर्ज की है, जिसमें पाँक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन आरोपी पर कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बल्कि बृजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में श्रजन चेतना महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। रैली का असल उद्देश्य क्या है, यह पता नहीं। लेकिन माना जा रहा है कि इस आयोजन के बहाने भाजपा सांसद हिंदू धार्मिक नेताओं की मदद से लोगों को अपने पक्ष में लामबंद

करना चाहते हैं, ताकि सरकार उन पर कार्रवाई करने से बचे। बृजभूषण शरण सिंह के राजनैतिक महत्व को भाजपा जानती है, शायद इसलिए कोई कड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। भाजपा सांसद अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते आए हैं और 19 मई को उन्होंने फिर कहा कि सारा मामला गुड टच और बैड टच का है। कोई भी ये बताए कि कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, अगर एक भी मामला साबित हुआ तो मैं फाँसी पर लटक जाऊंगा। सांसद महोदय को यह पता होना चाहिए कि मामला साबित होने का सही स्थान तो अदालत है, लेकिन वहाँ तक तो बृजभूषण शरण सिंह तभी पहुँचेंगे, जब वे खुद जाएंगे या उन्हें वहाँ तक आने के लिए बाध्य किया जाएगा। फिर सजा होनी है या नहीं, यह तय करना भी माननीय न्यायाधीशों का कार्य है। देश में न्याय अगर किसी सांसद के शक्ति प्रदर्शन से या

पंचायतों से होने लगे तो फिर कानून व्यवस्था किस दुर्दशा को प्राप्त होगी, ये कल्पना ही कठिन है। महिला पहलवानों के हक में खाप पंचायतों ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस निष्क्रियता का परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुमकिन है राजस्थान चुनाव और अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार कोई कदम उठा ले। लेकिन इसमें इंसाफ की जगह राजनैतिक स्वार्थ की भावना हावी रहेगी। सरकार अगर जनवरी से ही इस बारे में कोई पहल करती तो माना जा सकता था कि उसका इगदा इंसाफ करने का है, अब तो हर कदम भरपाई ही लगेगा, बशर्ते कोई कदम सरकार उठाए। महिला पहलवानों के लिए तो खाप पंचायतें आगे आ गईं, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में इसी तरह महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की कुछ महिला कलाकारों ने शो के निर्माताओं पर मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कलाकार ने कहा कि शो का सेट पुरुषवादी है, यहाँ पुरुष कलाकारों को अधिक पारिश्रमिक मिलता है, वे अपना काम करके जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन महिला कलाकारों को इंतजार कराया जाता है। रलैमर की दुनिया से लेकर अखाड़े तक महिलाओं की व्यथा एक जैसी ही है। क्या हालात सुधारने के लिए हमें फिर कोई राजा राममोहन राय जैसी शख्सियत चाहिए या देश के कानून इसके लिए पर्याप्त होंगे, यह विचारणीय है।

नवनिर्वाचित मेयर और चेयरमैन की शपथ के साथ लगेगी पाठशाला

लखनऊ (यूएनएस)। नगरीय निकाय चुनाव के 13 मई को परिणाम आ चुके हैं। अब तैयारी है नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के साथ पहली बैठक की। पहली बैठक के साथ ही निकायों का कार्यकाल शुरू होगा। 29 मई को यूपी में नगरीय निकाय के शपथ ग्रहण की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था। यूपी में नगरीय निकायों की संख्या 760 है जिसमें 14684 पदों पर हुआ है निर्वाचन। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ ही सबसे बड़ा नगरीय निकाय वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। जिसमें 17 नगर निगम, 199 पालिका परिषद अध्यक्ष और 544 नगर पंचायतें हैं जिसमें मेयर चेयरमैन अध्यक्ष मिलाकर 14684 पद हैं। पहले चरण का चुनाव 4 मई और दूसरे चरण का चुनाव 11 मई और 13 मई को रिजल्ट आया था। उत्तर प्रदेश के 760 नगरीय निकाय क्षेत्र में 4 करोड़ 32 लाख 39 हजार 647

**29 को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम कर सकते शिरकत
यूपी निर्वाचन आयोग आज सरकार को सौपेगा चुनाव रिजल्ट
जून माह में ही निकायों की पहली बैठक कराने की तैयारी**

मतदाता है जिसमें 2 करोड़ 29 लाख 87 हजार 955 पुरुष मतदाता और दो करोड़ 2 लाख 51 हजार 692 महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में 52.4 फीसदी मतदान हुआ था। प्रदेश में 75 जनपदों में 760 अध्यक्ष और 13924 सदस्यों के पदों पर चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में 760 नगरीय निकाय हैं, यूपी राज्य निर्वाचन आयोग कल 6 सोमवार को नगरीय निकाय का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगा। परिणाम आयोग से मिलते ही नगर विकास विभाग एक हफ्ते में नगरीय निकायों को शपथ ग्रहण कराने के कार्यक्रम जारी करेगा। उम्मीद की जा रही है कि 29 मई को यूपी के नगरीय निकायों में शपथ ग्रहण हो

सकता है। शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश के सभी मेयर और चेयरमैन की पाठशाला लगेगी। मेयर और चेयरमैन की पाठशाला लखनऊ में लगाने की तैयारी है। बताया जाएगा कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, निकायों में सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों से उम्मीदवारों की अधिकृत सूची लेकर उसका मिलान करा चुका है। अब नगर विकास विभाग को सूची मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जिसके बाद नगर विकास विभाग 5 वर्ष के लिए निकाय गठन की अधिसूचना जारी करेगा। निकायों के

गठन के बाद नगर निगम पालिका परिषद और नगर पंचायतों में शपथ ग्रहण के साथ सदन और बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग कोशिश कर रहा है कि यह बैठक जून में ही बुलाई जाए ताकि जिस दिन बोर्ड या सदन की बैठक होगी उसी दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल भी माना जाएगा। मतलब सीधे तौर पर मई महीने में शपथ ग्रहण तो वही जून के महीने में कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक बुलाने की योजना है ताकि निकायों का कार्यकाल एक साथ शुरू हो और एक साथ खत्म नगर विकास विभाग मेयर और चेयरमैन की पाठशाला में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी में जुटा है। शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश

सरकार नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों की पाठशाला लखनऊ में लगाने जा रहा है, जिसमें उनके अधिकारों, निकाय की कार्यप्रणाली के बारे में बताया जाएगा। सरकार की योजना का लाभ कैसे जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है उसकी जानकारी दी जाएगी, कैसे निकाय काम करेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। नगर विकास विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसको लेकर तैयारियां नगर विकास विभाग कर रहा है। 29 मई को शपथ और 30 या 31 मई में मेयर और चेयरमैन का प्रशिक्षण कार्यक्रम लखनऊ में होगा। नगर विकास विभाग जून में निकायों की पहली बोर्ड बैठक बुलाने की तैयारियां नगर विकास विभाग कर रहा है, ताकि समय से सभी नगर निकायों का कार्यकाल शुरू हो जाए क्योंकि पहले ही आरक्षण विवाद के चलते नगरीय निकाय के चुनाव काफी लेट हो चुके हैं।

कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी में योगी, बड़े बदलाव की संभावना

लखनऊ (यूएनएस)। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। फेरबदल पिछले एक साल में मंत्रियों द्वारा उनके विभागों में किए गए कार्यों और हाल के नगर निगम चुनावों में मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, कुछ मंत्रियों को पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि कुछ वरिष्ठ लोगों को संगठनात्मक कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। पार्टी और मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा मंत्री सरकार या पार्टी के लिए अधिक उपयुक्त है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी बदलकर पार्टी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को लगातार सतर्क रखना चाहती है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी और राज्य सरकार को कुछ मंत्रियों और सांगठनिक नेताओं के कुछ जिलों में तत्परता से काम नहीं करने की सूचना मिल रही है। पदाधिकारी ने कहा, पार्टी हाल के नगर निगम चुनावों में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही है। पूरा डेटा मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया जाएगा, इसके बाद कैबिनेट

फेरबदल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल



करने के फैसले से लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और पार्टी के ढांचे में बहुप्रतीक्षित बदलाव की शुरुआत हुई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शन करने में विफल रहे कुछ हाई-प्रोफाइल मंत्रियों को पार्टी में संगठनात्मक पदों पर स्थानांतरित किया जा सकता है और नए लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा। अपने स्वयं के उत्कृष्ट

प्रदर्शन को देखते हुए, मुख्यमंत्री को यह चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है कि किन मंत्रियों को हटाया जाना है और किसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने के बाद योगी सरकार का यह पहला कैबिनेट फेरबदल होगा। सूत्रों ने कहा कि जो मंत्री विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष के अभियान का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं, वे फायरिंग लाइन पर होंगे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा द्वारा खतौली विधानसभा सीट हारने और पिछले साल हुए उपचुनावों में मैनपुरी के सपा के गढ़ में संध लगाने में विफल रहने के बाद राज्य सरकार मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की योजना बना रही थी। उपचुनावों में समाजवादी पार्टी से दो निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने के बावजूद, भाजपा, आजमगढ़ और रामपुर को चुनौतीपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र के रूप में मानती रही है।

मण्डल स्तरीय उद्योग को लेकर क आयुक्त सभागार में जूम के माध्यम से हुई बैठक

लखनऊ (यूएनएस)। मण्डलायुक्त डा. रोशन जैकब ने मण्डल स्तरीय उद्योग के सम्बन्ध में बैठक आयुक्त सभागार में जूम के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा विगत माह में आयोजित इन्वेंस्टर्स समिट के अर्न्तगत जो भी एमओयू हस्ताक्षर किये गये थे। उनकी स्थिति की जानकारी मण्डल के सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त की। इस अवसर पर सम्बन्धित जनपदों के अपर जिलाधिकारी, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अघोषित बिजली कटौती होना भाजपा सरकार की खासियत: अखिलेश यादव



लखनऊ (यूएनएस)। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, आग बरस रही है और पारा चढ़ता ही जा रहा है। जनता परेशान है पर भाजपा सरकार की संवेदनहीनता की हद यह है कि वह बिजली संकट के समाधान की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। जब राजधानी लखनऊ में ही बिजली अक्सर गायब रहने लगी है तो अन्य जनपदों के हालात के बारे में क्या कहना? हैं तो जांच के नाम पर उल्टे शिकायतकर्ता को ही परेशान करने के हथकंडे अपनाए जाते हैं। गलती से बिल ज्यादा ही क्यों आता है, कम क्यों नहीं आता? अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने शासनकाल की कथित उपलब्धियों को विश्वस्तरीय बताते रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी जाकर हवाई दावे करते रहते हैं, पर उत्तर प्रदेश में उनकी पोल तो तब खुल जाती है जब सरकारी कार्यक्रमों में भी बिजली ऐन मौके पर गुल हो जाती है। जमीनी हकीकत और कथनी-करनी में फर्क जगजाहिर है। अखिलेश यादव ने कहा

कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट से व्यापारी परेशान हैं। छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किसान की फसल बर्बाद हो रही है। घरों में सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और महिलाएं हो रही हैं। घर में कूलर और एसी कैसे चले जब बिजली की आवाजाही ही होती रहे? ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समय मक्का की फसल खेतों में खड़ी है। इसको पानी की ज्यादा जरूरत है पर बिजली दो-तीन घंटे ही आती है। हर वर्ष गर्मी बढ़ने के साथ अघोषित बिजली कटौती होना भाजपा सरकार की खासियत है। अधिकारी लाईने ओवरलोड होने की बात करते हैं पर उसका इंतजाम नहीं करते हैं। इन दिनों ट्रांसफॉर्मर फुंकने की भी खबरें आ रही हैं। इनके रखरखाव में लापरवाही और उपकरणों की गुणवत्ता में खराबी देखने वाला कोई नहीं? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने छह वर्ष के कार्यकाल में एक ही काम किया है, समाजवादी सरकार के कामों पर अपने नाम की मुहर लगाना या फिर उन्हें बर्बाद कर देना।

कुछ लोगों को देर से समझ आती है अपनी गलती: अखिलेश

इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता : स्वामी प्रसाद

लखनऊ (यूएनएस)। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। इस घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 2 हजार के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपये के नोट के मामले में ऐसा ही हुआ है लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। ट्वीट में सपा प्रमुख ने कहा है, शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। वही समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, 2 हजार



रुपये की नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार कालेधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या भाजपा बताएगी की केंद्र व तमाम प्रदेशों में भाजपा की ही सरकार है तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार एवं कालाधन संभव कैसे हुआ ? इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता ? हालांकि आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को जारी बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2,000 रुपये के



नोट बदले जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये के नोट ही बदले जाएंगे। केन्द्रीय बैंक ने लोगों से बैंक जाकर 2,000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा है। लोग किसी भी बैंक शाखा में 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2,000 रुपये के नोट को बदलने की सुविधा दी जाएगी। आरबीआई के मुताबिक 2,000 रुपये के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और उनका चार-पांच साल का अनुमानित जीवनकाल खत्म होने वाला है।

पुलिस की गाड़ी ने मासूम को मारी टक्कर, परिवार के लोगों ने किया हंगामा

सीतापुर (यूएनएस)। जिले में पुलिसकर्मियों की प्राइवेट कार से एक हादसा हो गया। यहां एक बच्चे को पुलिस के वाहन ने टक्कर मार दी। दुकान जा रहे 8 साल के बच्चे की पुलिसकर्मियों की प्राइवेट कार से टक्कर लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने सिपाही के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सिपाही के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मामला तालगांव थाना इलाके का है। यहां पुलिसकर्मियों की एक प्राइवेट कार से मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गयी। मिली जानकारी के मुताबिक, मासूम अल्केश दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी तालगांव कोतवाली में तैनात सिपाही नीरज कुमार क्षेत्र से ड्यूटी करके वापस अपनी प्राइवेट कार से अकबरपुर तालगांव मार्ग पर तेज रफ्तार में आ रहे थे। तभी राम बाग के निकट बालक अल्केश को गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी की चपेट में

आकर मासूम गम्भीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे के बाद घायल मासूम बच्चे को पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंटी इलाज के लिए ले गया। जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर सीएचसी पहुंचे परिवारीजनों ने काफी हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के पिता की

तरफसे पुलिसकर्मियों नीरज कुमार के विरुद्ध कोतवाली प्रभारी को लिखित तहरीर दी गई है। जिसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया शव को पीएम के लिए भेजा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर केस दर्ज किया गया है।

2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने से पहले इसके प्रभाव का अध्ययन जरूरी: मायावती

लखनऊ (यूएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की घोषणा को जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला फैसला बताते हुए रविवार को कहा कि ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव एवं परिणाम का समुचित अध्ययन जरूरी है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया, "मुद्रा और वैश्विक बाजार में उसकी कीमत का संबंध देश के हित एवं प्रतिष्ठ से जुड़े होने के कारण इसमें जल्दी-जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मायावती ने सलाह देते हुए कहा, "इसीलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव एवं परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। अखिलेश्वरीय है कि आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे।

अरबों रुपये की जमीन पर मिलेगा अवैध कब्जा

लखनऊ (यूएनएस)। दबंगई, सत्ता का संरक्षण और चंद रूपयों से हथियवाई गई जमीन का बड़ा खेल नगर निगम में शामिल नव विस्तारित नगर निगम सीमा के 88 ग्रामों में नगर निगम के अप्सरों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए नगर निगम के जो वर्तमान प्रयास हैं वह सतही हैं। इसके लिए नगर निगम को व्यापक स्तर पर हर जोन में सप्ताहिक अभियान चलाना होगा। इसके लिए नगर निगम के समस्त जोनों की एक टीम बनाकर स्थानीय स्तर पर जानकारीयों एकत्रित करनी होगी। ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पर अभी जो एक दो मामले गांवों पर सतही तौर पर अवैध कब्जे के दिखाई दे रहे हैं वह दर्जनों की संख्या में समाने आएंगे। यानि कि एक सफल अभियान को चलाकर नगर निगम इतनी अधिक धनराशि वाली अपनी अवैध कब्जे वाली जमीन को वापस ला सकता है जिस धनराशि से उक्त नव विस्तारित ग्रामों में 50 प्रतिशत सुविधाएं तत्काल प्रभाव से जुटाई जा सकती हैं।

इस संबंध में पूर्व प्रधानों एवं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त 88 ग्रामों का नगर निगम सीमा से पूर्व प्रधानों का एकाधिकार था। अमूनन जिला स्तर पर प्रशासनिक अमला ग्रामों में चल रही भूमापिमाओं और स्थानीय दबंगों की अवैध कब्जेदारी पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे में दबंगों, सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोगों ने लेखपालों आदि को मिलाकर, कुछ खर्च करके या धमका कर बड़ी बड़ी जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग, पशुशाला, खेती या मकान बना डाले।

रेलवे को चलाना चाहिए अभियान

लखनऊ। राजधानी में रेलवे लाइन के किनारों केवल झुग्गियां नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हवेली एवं व्यवसायिक गतिविधियां रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। रेलवे के अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिल जाएगा। रेलवे द्वारा बीच बीच में कुछ अभियान तो चलाया जाता है लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया जाता है। बहुत समय पहले अभियान चलाकर कुछ अवैध निर्माण तोड़े गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुनः उक्त अवैध निर्माण हो गए। रेलवे के किनारों अवैध कब्जे ही नहीं बल्कि केवल की सामग्री का उपयोग भी इन अवैध कब्जेधारियों द्वारा किए जाने की चर्चा आम बात है। ऐसे में रेलवे प्रशासन को भी एक अभियान ऐसा चलाना चाहिए जो अनवरत जारी रहें।

यूपी का अगला चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी आप: केजरीवाल

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अगर किसी राजनीतिक दल ने अपने परिणामों से सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वह आम आदमी पार्टी है जिसके 100 से ऊपर प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नवचयनित चेयरमैन और सभासदों के साथ यूपी प्रभारी संजय सिंह की उपस्थिति में मुलाकात कर जीत की बधाई दी और मजबूत संगठन निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा जितने भी उत्तर प्रदेश में चेयरमैन और सभासद जीत कर आए हैं वह बहुत अच्छा काम करें ताकि आपके काम की खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश में फैले। उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और मैं भी वहां आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है लेकिन आप सभी ने जिस निष्ठा, लगन और ईमानदारी से चुनाव लड़ा और जीते ये आने वाले समय के लिए बड़े परिवर्तन की निशानी है जो विकास और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। आम आदमी पार्टी ने देश में राजनीति की परिभाषा बदल कर रख दी है।

रुपये नहीं मिलने पर राजमिस्त्री ने लगाई फांसी

फर्रुखाबाद। शराब के लिए रुपये नहीं मिलने पर राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले राजमिस्त्री ने पत्नी व बच्चों को गाली-गलौज कर घर से निकाल दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भखुरामऊ निवासी राजमिस्त्री सरवन कुमार शाक्य (46) शराब पीने का आदी था। शुक्रवार की शाम को सरवन कुमार ने बेटे शिवा व पत्नी निर्मला से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। पत्नी व बेटे ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इस पर सरवन का पत्नी व पुत्र से विवाद हो गया। सरवन ने गाली-गलौज कर पत्नी निर्मला, पुत्र शिवा, ऋषभ, पुत्री पूजा को घर से निकाल दिया। इसके बाद सरवन ने आंगन में लगे बकैना के पेड़ पर पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर उस पर लटक गया। रात को पत्नी व बच्चे वापस आए तो सरवन को फंदे पर लटका हुआ पाया। पत्नी निर्मला ने पुलिस का सूचना दी।

करो या मरो की स्थिति में होगा 2024 का चुनाव: केशव



**बीजेपी के खिलाफ अंदर से एक हैं विपक्षी: डिप्टी सीएम
काम कर रही डबल इंजन की सरकार
2 हजार का नोट बंदी की सूचना से भ्रष्टाचारियों के घर लगी आग**

लखनऊ (यूएनएस)। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम ने कहा, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी अंदर से एक हैं। विपक्ष के पीछे भारत विरोधी ताकतें भी हैं। आज शनिवार की सुबह 11.05 बजे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकाप्टर बुलंदशहर पुलिस लाइन में उतरा। उप मुख्यमंत्री की अगुवानी में जिले के आला अप्सर और भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा पार्टी कार्यालय

में पहुंचकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में जीत के लिए सभी को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व की अगुवाई में निकाय में जीत दर्ज की। कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान चल रहा है। इसको सफल बनाना है। 2024

की तैयारी शुरू हो गई है। बुलंदशहर में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, दोनों को फिर जिताना है। विपक्षी दल अंदर से एक हैं, जो भाजपा के खिलाफ एक हो रहे हैं। विपक्ष के पीछे भारत विरोधी ताकतें भी हैं। हम अपने प्रयास और परिश्रम से फिर से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर विजय से ग्राम करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में सपा की गुंडागर्दी थी। आखिर कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर कमल खिला दिया। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार के कार्यकाल में चुनाव हुआ, लेकिन भाजपा ने जीत दर्ज की। डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 सीटों का

लक्ष्य लेकर मेहनत करनी है। 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति में होगा। टिकट न मिलने को लेकर नाराजगी न रखें। टिकट वितरण में 19-20 हो ही जाता है। आज गुंडे भय से कांपते हैं। आज प्रदेश को सुरक्षा का माहौल है, जिनकी पार्टी के नेता गुंडे अपराध और माफिया हो, वह क्या सुरक्षा देंगे। नाराजगी प्रकट करने का समय 2024 की जीत के बाद आएगा। 2024 तक एक ही लक्ष्य कमल खिलाना है। कहा कि मैं कार्यकर्ता पहले हूँ और उपमुख्यमंत्री बाद में। कार्यकर्ता अपने को उपमुख्यमंत्री से कम न समझे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2000 का नोट बंद करने की सूचना से भ्रष्टाचारियों के घर आग लग गई। दुनिया का एक से एक शक्तिशाली देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी से हाथ मिलाता है। सीमा पर पहले संकट का सामना करना पड़ता था। सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं। 2017 से पहले बुलंदशहर में कितनी बिजली आती थी आपको याद होगा, अब आपको पता ही नहीं चलता बिजली जाती कब है। पहले पुलिस अपराधियों से डरती थी अब अपराधी पुलिस से डरते हैं। छह साल जितना काम भाजपा ने प्रदेश में किया है। इतना सपा-बसपा 60 साल में भी नहीं कर पाते। पहले ट्रांसफॉर्मर बिना रिश्तत दी नहीं लगता था। अब 24 घंटे में बिना पैसे दिए ट्रांसफॉर्मर लगता है। निजी नलकूपों का बिल माफ कर दिया। उज्जवला के दो गैस सिलेंडर भरने का काम भी प्रदेश सरकार करेगी।

ट्रेनों में निर्धारित मूल्यों पर चीजों को लेने के लिये अभियान की शुरुआत

लखनऊ (यूएनएस)। ट्रेनों में इण्डियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की दी जाने वाली खान-पान एवं अन्य चीजों को खरीदने एवं मेन्यू में अवांछित चीजें शामिल कर ज्यादा भुगतान के वसूली को रोकें जाने एवं निर्धारित मूल्य पर सामानों को लेने के लिये यात्रियों को जागरूक करने के लिये एक बार फिर अभियान की शुरुआत की गयी है। एमआरपी पर खाना दो अभियान की शुरुआत करने वाले जी बिजनेस के प्रबन्ध सम्पादक अनिल सिंघवी ने बताया कि जी बिजनेस की जिम्मेदार पत्रकारिता लगातार तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करती है जिससे उपभोक्ता अधिकारों को समय-समय पर सहयोग मिलता है। ट्रेनों में खाने की चीजें खरीदने या मेन्यू में अवांछित चीजें जुड़ जाने के कारण ज्यादा दाम वसूले जाने की खबर हमारे द्वारा की गई खोजी पत्रकारिता और उपभोक्ता जागरूकता कैंपेन के कई प्रभावी उदाहरणों में से एक है हम आगे भी अपने दर्शकों और साझीदारों से जुड़े रहेंगे, ताकि सही समय पर पूरी समझदारी से फैसले करने में सभी की मदद की जा सके।

पैट्री से आईआरसीटीसी के तय दामों से ज्यादा पर खाना बेचा जा रहा था। एमआरपी पर ध्यान न देने के

चलते वेंडर गलत फायदा उठा रहे थे और खाने की चीजों के लिये यात्रियों से ज्यादा पैसे ले रहे थे मतलब यात्री असल एमआरपी से 50 रुपये ज्यादा दे रहे थे जी बिजनेस की उपभोक्ता पर केंद्रित इस न्यूज स्टोरी का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने दर्शकों को उन जिम्मेदारीपूर्ण पहलों पर शिक्षित किया जा सके जिन पर उपभोक्ता और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जी बिजनेस ने दर्शकों को ट्विटर पर एमआरपी पर दो खाना हैशटैग का इस्तेमाल कर ज्यादा कीमत वसूलने की ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित किया और आईआरसीटीसी को भी तुरंत कार्रवाई के लिये सचेत किया

अपशिष्ट बड़ी ने वेंडरों के लिये भी एक आदेश जारी किया और कहा कि वे ज्यादा दाम लेना तुरंत बंद करें और ज्यादा दामों को उचित ठहराने के लिये खाने के साथ पानी मिलाना बंद करें। आईआरसीटीसी ने पाँच जोन्स के ग्रुप जनरल मैनेजर्स को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने और इस पर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। वेंडरों को 'एला कार्टें' सिस्टम बंद करके चेताया भी गया। यात्रियों की असुविधा का संज्ञान लेते हुए, आईआरसीटीसी जाँच के लिये 10 रुट्स पर ट्रेनों को चुनेगा और भीड़ वाले रुट्स पर औचक निरीक्षण होंगे।

गली निर्माण कर रहे मजदूरों को फावड़ा लेकर दौड़ाया

फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायत की गली निर्माण करते वक्त कुछ दबंगों ने मजदूरों से गाली-गलौज की। बाद में फावड़ा लेकर दौड़ा लिया। सरकारी काम बंद करवाने के बाद जान से मारने की धमकी दी। प्रधान के देवर ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मऊदरवाजा थाने के गांव हाथीपुर में ग्रामसभा की ओर से गली का निर्माण चल रहा है। शुक्रवार सुबह मजदूर काम कर रहे थे। उसी वक्त मोहल्ले के ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जब ग्राम प्रधान शबाना बेगम के देवर अतीक खां ने रोका, तो वह गाली-गलौज करने लगे। दबंगों ने फावड़ा फेंक दिए। कुछ लोग फावड़ा लेकर मजदूरों को मारने के लिए दौड़े। अतीक खां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही आजम खां, इदरीश, शकील, शब्बीर, जाकिर खां, शराकत खां, जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव

लखनऊ (यूएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण बनाने संबंधी अध्यादेश जारी किये जाने के बाद अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और कहा कि यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया, "दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक-अन्याय का भी। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, "भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीट पर उसकी करारी हार होगी, इसीलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है। गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आईएएस और दिल्ली, अंडमान निकोबार दीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव प्रशासनिक सेवा कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया। यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छेड़कर बाकी

सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक समाह बाद उठाया गया है।



स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सुधा द्विवेदी द्वारा राज तरुण ऑफसेट, एल.जी.एफ. 4-5, अंसल सिटी सेंटर, निकट यू. पी. प्रेस क्लब, हजरतगंज, लखनऊ से मुद्रित तथा 499/1, विनय विहार कालोनी, इन्दिरा नगर, निकट-बी.आर. इंटरनेशनल स्कूल, पो. सीमैप, लखनऊ-226015 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

सम्पादक- सुधा द्विवेदी
कार्यकारी सम्पादक
डॉ. एस.के.गोपाल
प्रबंध सम्पादक
होमेन्द्र कुमार मिश्र
विशेष संवाददाता
सुनील कुमार सिंह
संवाददाता

जादूगर सुरेश कुमार
सम्पर्क : 9451532641,
8765919255

ईमेल : janveennews@gmail.com

RNI No. UPHIN/2011/43668

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।